नदियों के जल का अधिकतम उपयोग

755. **श्री अनंतराव देवशंकर घबे:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की प्रमुख नदियों में अनुमानत: कितना-कितना जल प्रवाहित हो रहा है;

(ख) सिंचाई, पेयजल तथा औद्योगिक कार्यों के लिए अलग-अलग कितने-कितने जल का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) कितना जल बेकार में समुद्र में बह जाता है;

(घ) इन नदियों के जल के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने जल संग्रह के लिए कोई विस्तृत ब्यौरा तैयार किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगा नायडू): (क) से (ग) देश की मुख्य नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है। वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन जो लगभग 452 बिलियन घन मीटर है, के अलावा उपयोज्य सतही जल 690 बिलियन घन मीटर आंका गया है। जल (सतही एवं भू) का वर्तमान (1994) उपयोग लगभग 606 बिलियन घन मीटर है जिसमें से 536 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल का उपयोग नहीं किया गया।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल का मौजूदा (1994) उपयोग निम्न अनुसार है:

प्रयोजन	उपयोग (बिलियन घन मीटर)
सिंचाई	501.00
घरेलू	30.40
ऊर्जा	20.20
उद्योग	20.00
अन्य	34.00
	605.00
	अर्थात् 606

(घ) और (ङ) पंचवर्षीय योजनाओं में नदियों पर भंडारणों के सृजन पर जोर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1989 तक लगभग 166 बिलियन घन मीटर की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन किया गया। 77 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए कोष विभिन्न अंतिम चरणों में है। इसके अतिरिक्त, वृहद और मध्यम योजनाओं के जरिए लगभग 130 बिलियन मीटर भंडारण बढ़ाए जाने के लिए योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों का अंत:संपर्क स्थापित करके और सम्भाव्य स्थलों पर भंडारणों का निर्माण करके अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का अंतरण करने की परिकल्पना की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अंत:बेसिन अंतरणों के जरिए प्रयोग के लिए 220 बिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा।

Drought in Karnataka

756. **SHRI JANARDHANA POOJARY:** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount of loss suffered by Karnataka due to drought during the current year; and

(b) the amount of relief provided by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) As the South-West monsoon, 1995 is still in progress, it is too early to estimate at this stage the impact of drought conditions in Karnataka.

(b) Government of India has released two instalments of Central share of Calamity Relief Fund amounting to Rs. 14.81 crores during 1995-96 to the State Government.

Furnishings at Residences and Offices of Ministers

757. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the furniture and other items provided at Government expense, at the offices and residences of the Ministers, are returned to CPWD on their relinquishing offices as Ministers;

(b) if so, the details of the prescribed rules and procedures in this regard; and

(c) how far these rules have been followed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFARIS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) The furniture and other items for offices are supplied by the respective Ministeries. For residences, furniture and electrical appliances are supplied by the CPWD, which are generally returned by the Ministers within one month of their relinquishing the office.

(b) and (c) The supply of furniture and electrical appliances to a Minister and recovery of rent therefore is governed by the provisions of Ministers Residence Rules, 1962.

Solution to Indo-Bangladesh River Water sharing dispute

758. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken by Government to revive the Water Panel by calling a meeting of the Joint Rivers Commission, formed by India and Bangladesh which did not meet in the past Five years to resolve the issue of sharing water of common rivers; and

(b) if so, when the decision is likely to be implemented by the two Governments, to arrive at a permanent solutions to the problem of water sharing?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU) (a) and (b) the Union Government has decided to revive the talks with the Government of Bangladesh on water sharing by calling for a meeting of the Joint Rivers commission in Delhi very soon. Discussions for solution to the problem of water sharing and other related isues are scheduled to be held during this meeting.

---

12 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

The Deputy Chairman in the chair

Notifications of Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture and Cooperation) together with Corrigendum.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): Madam, I lay on the Table—

A copy each (in English and Hindi) of